

3. As I have already stated, the 'Own Your Home' Scheme of the L.I.C. has not been extended to the rural areas. At present the Corporation does not contemplate extending the Scheme to rural areas because these areas do not satisfy the criteria laid down by it.

have returned to normal, Government have now reviewed the position. All the remaining employees still under suspension will now be reinstated. Orders to this effect are under issue. This will of course be without prejudice to the cases pending in courts, or under departmental proceedings or to their liability for appropriate disciplinary action under the service rules.

14 hrs.

STATEMENT REGARDING CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES' STRIKE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, as the House is aware, Government have reviewed from time to time their original orders regarding action to be taken against Central Government employees who participated in the illegal strike of 19th September, 1968, and have announced several relaxations. All those who were not charged with violence, intimidation or active instigation have been reinstated. Temporary employees discharged under similar circumstances have been taken back in service. After taking all the circumstances into consideration particularly the fact that these employees have now been under suspension.

Those employees who participated in the strike and were absent from duty have suffered a 'break in service' under the normal operation of the rules. The hardships suffered as a consequence have been greatly mitigated by subsequent relaxations. Government have also decided that the break in service should now be condoned with immediate effect without, of course, reopening any adverse effect that might have already undergone. The days of absence will be treated as *dies non*.

It has further been decided that the fact of the participation of the employees in the last strike would not henceforth be taken into account for purpose of their confirmation, declaration of quasi-permanency or promotion.

अध्यक्ष महोदय : इस को आप टेबिल पर रख दीजिए ।

SHRI NATH PAI (Rajapur) : We want to ask some questions, if you will permit us. So, let him place the statement here; tomorrow, if you permit, we could put questions.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

MR. SPEAKER : I think all of us are sitting here waiting for the adjournment for lunch. (Interruptions) All right; we can wait; let him proceed.

श्री नाथ पाई : आज यहाँ पटल पर रख सकते हैं, सवाल हम कल पूछेंगे ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : After taking all the circumstances into consideration, particularly the fact that these employees have now been under suspension for about a year and a half and conditions

SHRI NATH PAI : Sir, one small clarification. We welcome the statement so far as it goes to mitigate the hardships for the exercise of the legitimate rights guaranteed by our Constitution, namely, to withhold work which is technically called a strike. But he made a very slight reference to one of the hardships caused by break in service having been mitigated. He knows how great is the hardship. We would like to ask him whether the effect of the break in service cannot be completely eliminated. I do not mean in the past, but in future. (Interruptions) You have given it ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is clear. What happened in the past will not be reopened. In future there would be no disability.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट चाहिए । यह बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है । देर से सही, सरकार ने एक ठीक फैसला किया है लेकिन जो मामले अदालत में पड़े हैं उनका क्या होगा । झूठे

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is clear. What happened in the past will not be reopened. In future there would be no disability.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट चाहिए । यह बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है । देर से सही, सरकार ने एक ठीक फैसला किया है लेकिन जो मामले अदालत में पड़े हैं उनका क्या होगा । झूठे

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मुकदमों में कर्मचारियों को फसाया जा रहा है।
(*Interruption*)

MR. SPEAKER : I do not allow all this.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : दिल्ली पुलिस वालों के कैसेज भी विदवा किए जायं।
... (ब्यवधान) ...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : दिल्ली पुलिस के जो कैसेज बाकी रह गए हैं उनको भी विदवा कर लिया जाये। ... (ब्यवधान) ...

MR. SPEAKER : Order, order.

14.05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till five minutes past Fifteen of the Clock.

— — —

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now resume further discussion on the President's Address. Mr. Shiv Kumar Shastri may continue his speech.

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार किसानों और मजदूरों के हित सम्पादन का वर्णन करते करते नहीं थकती किन्तु वह हित किस प्रकार से किया जा रहा है, इस का एक उदाहरण हम ने गंगानगर में जाकर अपनी आंखों से देखा। वहाँ जो सत्याग्रह चल रहा है वह बहुत ही शांतिपूर्ण है। किन्तु किस प्रकार सुल्हाड़िया की सरकार ने उन सत्याग्रहियों पर अत्याचार किये हैं, इसको वहाँ जानकर बहुत

दुःख हुआ। मैं यह कह रहा था कि अमर शहीद भगत सिंह के परिवार के प्रति सारे भारतवर्ष में आज भ्रगाघ श्रद्धा है। वहाँ पदम पुर में भगत सिंह की बड़ी बहन प्रकाश कौर ने सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया और जिस समय गंगानगर की भरी सभा में उन्होंने अपने घायल हाथों को दिखाते हुए कहा कि सुल्हाड़िया की पुलिस ने डंडों के प्रहार से मेरे हाथों को क्षत विक्षत कर दिया है तो चारों तरफ से सभा में शर्म शर्म के नारे गूँज उठे।

इसी प्रकार से अनेक अत्याचारों की कहानी हम ने वहाँ जाकर अपने कानों से सुनी। भादरा में जो गोलीकाण्ड हुआ उसके लिए यह बात कही गई है कि तहसील के करीब जा कर सत्याग्रहियों ने आक्रमण कर दिया था। जब हम ने स्थान को जाकर देखा तो जहाँ पर गोलीकाण्ड हुआ था वहाँ से लगभग आधे मील के फासले पर तहसील है। उन दोनों की संगति बिलकुल नहीं बनती। यही कारण है कि सुल्हाड़िया साहब यह स्वीकार करते हुए भी कि हम यहाँ जांच करायेंगे वह इस को करा नहीं रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके अत्याचारों का नग्न रूप जनता के सामने आ जायेगा अगर उन्होंने न्यायिक जांच करवाई।

इस प्रकार के तनाव और भगड़े केवल राजस्थान में नहीं हैं अपितु भारत में स्थान स्थान पर हैं। मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद इसी प्रकार का है। बम्बई में हड़ताल है। ऐसी स्थिति में यह उचित ही मांग की जा रही है कि एक उच्च अधिकारी की स्थायी समिति हो और उस में उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के जजों को नियुक्त किया जाये। जहाँ कहीं इस प्रकार की स्थिति हो वह उस का निपटारा करें। इस प्रकार से सारी परिस्थिति का नियन्त्रण और सन्तुलन हो। जिस प्रकार से हित सम्पादन करने की बात की जा रही है किसानों और मजदूरों का, वह केवल भाषणों